# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
## Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission


पत्रांक /Ref. No.: 2009 दिनांक /Date.: 23.02.2020

## (संवाद–28)

**उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की ओर से संबोधन।**

प्रिय अभ्यर्थियों,

सामान्यतया संवाद स्तम्भ पर आयोग के सचिव आपसे बातचीत करते हैं किंतु वन आरक्षी(फॉरेस्ट गार्ड) भर्ती परीक्षा में प्रकाश में आयी कुछ गड़बड़ियों की पृष्ठभूमि में आयोग के अभ्यर्थियों से मुझे स्वयं संवाद करने की आवश्यकता महसूस हुयी। मुख्य रूप से इसलिए कि प्रकाश में जो मामले आये हैं उनके संबंध में कुछ संगठन, समाचार पत्र एवं जन प्रतिनिधि भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार व बयानबाजी कर रहे हैं।

मैं प्रारम्भ में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आयोग ने वर्ष 2015 से परीक्षा कार्य प्रारम्भ किया व आज की तिथि तक आयोग 66 परीक्षायें करा चुका है। आयोग के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी परीक्षायें होने के बाद भी यह पहला अवसर है कि जिसमें परीक्षा कक्ष में मोबाइल के प्रयोग की या ब्लूटूथ डिवाइस के उपयोग की शिकायत मिली है। एक अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल का उपयोग प्रश्न पत्र की समाप्ति के बाद 4 बजे किया गया। इसकी पुष्टि होने पर आयोग द्वारा उस अभ्यर्थी को भी 3 वर्ष के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच पुलिस के साइबर सेल द्वारा की जा रही है। यदि इसमें किसी अन्य अभ्यर्थी या परीक्षा केन्द्र की लापरवाही मिली तो उनके विरूद्व भी कठोर कार्रवाई की जायगी। यह भी स्पष्ट करना है कि जिन केन्द्रों में मोबाइल के उपयोग या ब्लूटूथ के उपयोग की बात आई है उनमें भी पुलिस बल तैनात था। ब्लूटूथ का उपयोग घरों में चोरी करने जैसा है व ये अपराधी या गिरोह केवल उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय है किंतु इस बार हमारी जांच एजेंसियों ने पर्याप्त तत्परता दिखाते हुये जो कार्रवाई की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं व आशा करता हूं कि दोषियो के विरूद्व कठोर कार्रवाई होगी।

आयोग द्वारा वर्ष 2017 से परीक्षा की शुचिता तथा पारदर्शिता के लिए भी विशेष प्रयास किये गये है सभी अभ्यर्थी यह जानते हैं कि ओ0एम0आर0 शीट की तीन कापियों का प्रयोग केवल इस आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परीक्षा के तत्काल बाद उत्तर कुंजी का प्रकाशन, परिणाम आने के बाद सभी अभ्यर्थियों की मूल ओ0एम0आर0 शीट्स का वेबसाइट पर प्रकाशन, परीक्षा केन्द्रों के कंट्रोल रूम तथा परीक्षा के उपरांत आयोग स्तर पर होने वाली सारी कार्रवाई की वीडियोग्रॉफी सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

क्रमशः–––––(02)



राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com

परीक्षा संचालन के लिए सभी परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य परीक्षा संचालनकर्त्ताओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं जिसमें अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग के लिए भी विस्तृत निर्देश हैं।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि परीक्षा में जो भी नकल माफिया या गिरोह सक्रिय हैं वे पैसे के लिए कार्य करते है। आयोग की आंतरिक जांच से यह भी संकेत मिलता है कि प्रदेश के बाहर के गिरोह भी इस कार्य में संलग्न हैं। इसका मुख्य आधार पैसा देने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिभावक हैं। ऐसे साजिशकर्त्ता अभ्यर्थियों के मामले में भी आयोग कठोर कार्रवाई करेगा। मैं सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध करूंगा कि आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिम्मेदारी से व्यवहार करें तथा मेहनत व ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं व कर रहे हैं। अतः साजिश कर्त्ताओं का शिकार न बनें। परीक्षा माफिया बहुत दिनों से सक्रिय हो सकते हैं किंतु आयोग द्वारा अपनाई जा रही शुचिता व पारदर्शिता से उन्हें गंभीर परेशानियां हो रही है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का भी महत्वपूर्ण सहयोग आयोग को चाहिए।

इस परीक्षा को कुछ समाचार पत्रों ने पहले दिन ही घोटाला बता दिया व जन प्रतिनिधियों ने कहा कि पेपर लीक हो गया। अब तक इस मामले की जो जांच हुयी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि कुछ अभ्यर्थियों को नकल कराने का प्रयास किया गया है इसका वास्तविक स्वरूप क्या रहा यह हमारी जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। यह एक सीमित नकल का मामला लगता है व इसके लिए वर्तमान में परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूं कि परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर अभ्यर्थियों में भ्रामक तथ्यों को प्रसारित करने के बजाय परीक्षा को स्वच्छ बनाने में आयोग को सहयोग करें। आयोग एक स्वतंत्र निकाय है व इसका परीक्षा संचालन के मामले में राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा आयोग को जो सहयोग मिला है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग का नया कार्यालय भवन बन रहा है। आयोग 2014 में बना व 66 परीक्षाओं में से 63 परीक्षायें मार्च 2017 के बाद ही हुयी है। मार्च 2017 के पूर्व कुल लगभग 600 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हुयी थी किंतु मार्च 2017 के बाद लगभग 5000 से अधिक अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी। आयोग को सभी विषयों पर सरकार का सक्रिय सहयोग व मार्गदर्शन मिला है। मेरा मानना है कि चयन परीक्षाओं का मामला विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए व सभी को इसमें पारदर्शिता व शुचिता बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए।

क्रमशः———(03)

आयोग परीक्षाओं में और अधिक पारदर्शिता व शुचिता बढ़ाने की दृष्टि से निकट भविष्य में ऑनलाइन परीक्षायें प्रारम्भ करने की तैयारी कर रहा है। इससे वर्तमान तक प्रकाश में आई इन गड़बड़ियों को समाप्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही भविष्य में ऑफलाइन परीक्षाओं में जैमर के उपयोग को भी बढ़ाया जायेगा जिससे ब्लूटूथ व मोबाइल डिवाइस के प्रयोग को निष्प्रभावी किया जा सके।

एक तथ्य बार—बार मीडिया व समाचार पत्रों में आता रहा है कि आयोग की परीक्षाओं में बार—बार अनियमितताये या गड़बड़ी या घोटाला आ रहा है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक 66 परीक्षाओं में 06 परीक्षाओं में ही गड़बड़ी या अनियमितता की बात सामने आई है इनमें से 05 मामलों में आयोग ने **स्वयं** गड़बड़ियां पकड़ी हैं तथा इनके मुकदमे भी दर्ज कराये हैं। सहायक अध्यापक(एल0टी0) भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों का मामला, तकनीशियन ग्रेड—2 परीक्षा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा में मूल ओ0एम0आर0 में छेड़छाड करने के मामले आयोग ने ही पकड़े व उजागर किये। कनिष्ठ अभियंता(विद्युत/यांत्रिकी) की परीक्षा के संदर्भ में आयोग ने जांच की व परीक्षा निरस्त की तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी(वी0पी0डी0ओ0) पद के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं जाचं कराई गयी व आयोग द्वारा परीक्षा निरस्त कराकर पुनः स्वच्छ परीक्षा कराई गयी जिसकी अभ्यर्थियों ने काफी प्रशंसा की। ऐसे में आयोग के भीतर परीक्षाओं की शुचिता को लेकर विशेष सतर्कता रखी जा रही है। वर्तमान में वन आरक्षी(फॉरेस्ट गार्ड) पद पर आयी गड़बड़ी के संबंध में जांच के उपरांत कठोर कार्रवाई होगी। इससे स्पष्ट होगा कि आयोग परीक्षाओं की शुचिता के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है।

अंत में मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार व आयोग स्वच्छ परीक्षाओं के लिए कटिबद्व है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह निदेश व्यक्तिगत रूप से दिये है कि परीक्षा की शुचिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आयोग इसी के अनुरूप कार्रवाई कर रहा है। भ्रामक समाचारों, सोशल मीडिया संदेशों तथा अनावश्यक विरोधों से आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मनोबल पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। भर्ती परीक्षा कराना एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है एवं ये कार्य निरन्तर कराना है ऐसे में कोई भी सरकार हो आयोग का यह निरन्तर प्रसास है कि इसमें सुधार किया जाता रहे। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है तथा यह अपील है कि आयोग की परीक्षाओं में गैर कानूनी तरीकों को त्याग कर स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा व मेहनत के बल पर राज्य सरकार में सेवा का अवसर जीतें।

भविष्य की परीक्षाओं के लिए शुभकामना के साथ,

आपका,

(एस0 राजू)
अध्यक्ष।